



जबनाथक सभ्राट



बर्ष :13 अंक :328 पृष्ठ -4 दिनांक 01 दिसम्बर 2024 दिन रविवार

संभल हिंसा जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर 10 दिसंबर तक रोक

उत्तरप्रदेश में कल

का मौसम



1 दिसम्बर में उत्तर प्रदेश का तापमान काफी आरामदायक और न्यूनतम 15°C से अधिकतम 26°C रहता है। दिसम्बर के महीने में उत्तर प्रदेश में लगभग 3 से 8 दिनों की बारिश की उम्मीद कर सकते हैं।

दिल्ली में टूटा

रिकॉर्ड, 5 साल में

सबसे गर्म महीना

रहा नवंबर

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से वायु प्रदूषण लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। शनिवार को भी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में एक्यूआई 300 से ज्यादा मापा गया। वहीं 29 नवंबर की रात इस सीजन की अब तक की सबसे ठंड रात रही। हालांकि, सामान्य से अधिक गर्म महीना रहने का सिलसिला लगातार जारी है। इस साल नवंबर महीना पिछले 5 साल में सबसे गर्म रहा, जिसमें दिन और रात का तापमान सबसे अधिक रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार 2019 के बाद सबसे देरी से तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया है। साल 2019 में एक दिसंबर को तापमान 10 डिग्री से नीचे गया था। औसत न्यूनतम तापमान 14.9 नवंबर माह का औसत न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो दीर्घावधि औसत (एलपीए) 13 डिग्री सेल्सियस से लगभग दो डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसी प्रकार, औसत अधिकतम तापमान एलपीए से 1.1 डिग्री अधिक 29.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 2019 के बाद से सबसे गर्म नवंबर है। 25 नवंबर से तापमान में गिरावट जारी न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट 25 नवंबर को शुरू हुई। जब यह 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाओं तथा रात में साफ आसमान के कारण इसमें लगातार गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार 26 नवंबर को न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस, 27 नवंबर को 10.4 डिग्री सेल्सियस तथा 28 नवंबर को 10.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। शुक्रवार को इस मौसम में पहली बार तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मौसम की स्थिति के बारे में आईएमडी अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा ठंड नवंबर के अंत में सामान्य स्थिति है, लेकिन बारिश और बर्फबारी की कमी के कारण इस मौसम में कुल मिलाकर सामान्य से अधिक गर्मी बनी हुई है। उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण सप्ताहांत में रात्रि तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की अस्थायी वृद्धि होने का अनुमान है, तथा अगले सप्ताह की शुरुआत में उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण तापमान में कुछ और गिरावट आने का अनुमान है। 1951 के बाद अक्टूबर भी रहा था सबसे गर्म सामान्य से अधिक गर्म रहा, क्योंकि दिल्ली में 1951 के बाद से इस वर्ष सबसे गर्म अक्टूबर महीना दर्ज किया गया, जिसमें दिन और रात दोनों का तापमान औसतन सामान्य से लगभग दो डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में औसत मासिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35.1 डिग्री सेल्सियस और 21.2 डिग्री सेल्सियस था, जो 1951 में क्रमशः 36.2 डिग्री सेल्सियस और 22.3 डिग्री सेल्सियस के बाद सबसे अधिक था। सीजन की सबसे ठंड रात मौसम विभाग ने शनिवार को हल्का कोहरा छाप रहने तथा अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 26 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है। 29 नवंबर को अधिकतम तापमान 26.4 दर्ज किया गया जो सामान्य है। जबकि न्यूनतम तापमान 9.5 दर्ज किया गया जो सामान्य से एक डिग्री कम है। 29 नवंबर इस सीजन की सबसे गर्म रात दर्ज की गई।

संभल न्यूज संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्व को लेकर हुए पथराव और हिंसा के बाद प्रशासन ने 10 दि. संबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाके में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया है। जामा मस्जिद के सर्व के बाद भड़की हिंसा के बीच संभल जिला प्रशासन ने शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला प्रशासन ने शनिवार को आदेश जारी कर 10 दिसंबर तक जिले में बाहरी लोगों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले की सीमा में किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस कदम का



उद्देश्य क्षेत्र में शांति बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति को टालना है। इस आदेश के मद्देनजर आज समाजवादी पार्टी (सपा) का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संभल का दौरा नहीं कर सका। इस दल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे करने वाले थे। उन्होंने लखनऊ में अपने आवास पर पत्रकारों को बताया कि प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद ने फोन कर उनसे संभल न जाने का अनुरोध किया है। शांति और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने

शुक्रवार को राज्य सरकार को संभल में शांति और सौहार्द बनाए रखने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि शाही जामा मस्जिद के सर्व की रिपोर्ट को सील बंद रखा जाए और स्थानीय अदालत में इस मामले की कार्यवाही फिलहाल स्थगित रहे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, शांति और निष्पक्षता सुनिश्चित होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई गलत कदम उठाया जाए। जामा मस्जिद का सर्व के बाद भड़की हिंसा

19 नवंबर को स्थानीय अदालत ने शाही जामा मस्जिद के सर्व कराने का आदेश दिया। कुछ याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दावा किया कि मस्जिद की जगह पहले एक हरिहर मंदिर था। इस आदेश के बाद 24 नवंबर को हिंसा भड़क उठी, जिसमें पथराव की घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई और कई लोग जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं घायल हुए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। इस आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवा निवृत्त न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार अरोड़ा करेंगे। तनाव को देखते हुए जिले में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि हर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

यूपी में भैंस चरा

रहे युवक को पुलिस

ने थाने में ले जाकर

डंडों से पीटा,

रिश्त में लिए 1

लाख रुपये

यूपी के बलिया में नरही थाने में तैनात दो पुलिसवालों पर एक लाख रुपये की जबरन वसूली करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। एसपी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। ये वहीं नरही थाना है जहां पिछले दिनों पुलिसकर्मियों द्वारा रा. जाना ट्रकों से लाखों रुपये की अवैध वसूली का भी मामला सुर्खियों में रहा था। बताया जा रहा है कि नरही थाना क्षेत्र में भरौली निवासी रुदल यादव 25 नवंबर को अपने गांव के बागीचे में भैंस को चरा रहा था। तभी थाने पर तैनात सिपाही कौशल पासवान और ऋषिलाल बिंद ने रुदल यादव को उठा लिया और उसे थाने में ले आए। आरोप है कि यहां पर उन्होंने रुबल को एक कमरे में बंद कर दिया और डरा धमका कर उसे छोड़ने के लिए एक लाख रुपये वसूले। जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। जबरन वसूली मामले में दोनों निलंबित पीड़ित रुदल ने इस पूरे मामले की शिकायत एसपी विक्रांत वीर से की। एसपी ने जब मामले की जांच क्षेत्राधिकारी से कराई तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद एसपी ने इन दोनों कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दोनों कांस्टेबल को जेल भेज दिया। दल का कहना है कि जब वो अपनी भैंस चरा रहा था, तभी दो सिपाही आए और उससे पूछा की तुम्हारा भाई कहां है उस पर मुकदमा है। ये कहते हुए वो उसे उठा ले गए और थाने में ले जाकर उससे पैसों को मांग करने लगे। उन लोगों ने उसे डंडे से मारा तो उसने एक लाख रुपये मोबाइल से इनके बताए गए व्यक्ति के नंबर पर पैसा भेज दिया उसके बाद उन्होंने उसे थाने से जाने दिया। पीड़ित की शिकायत पर एसपी ने की कार्रवाई एसपी विक्रांत वीर ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि थाना नरही जनपद बलिया अन्तर्गत एक प्रकरण संज्ञान में आया जहां भरौली के रहने वाले रुदल यादव ने आरोप लगाया गया है कि थाना नरही पर कार्यरत 2 कांस्टेबल कौशल पासवान व ऋषिलाल बिन्द उसे खेत से उठा ले गए और डरा धमकाकर पैसों की वसूली की। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी सदर के द्वारा जांच कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया दोनों आरक्षियों की संलिप्तता पायी गई जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

विभाग से अधिकृत अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद तो वह फीस का हकदार, बकाया राशि देने का आदेश

याची को वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली व जौनपुर के गांव सभा का पैनाल अधिवक्ता नामित किया गया था। उसे गांव सभा की ओर से नोटिस लेने व प्रतिवाद करने के लिए अधिकृत किया गया था। इस दौरान वाराणसी, गाजीपुर व चंदौली के जिलाधिकारियों ने याची के बिलों का भुगतान कर दिया, लेकिन जौनपुर के डीएम ने नहीं किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी विभाग से अधिकृत अधिवक्ता ने कोर्ट में रहकर पक्ष रखा है तो वह फीस का हकदार है। कोर्ट ने जौनपुर के डीएम

को निर्देश दिया है कि गांव सभा के पैनाल अधिवक्ता के बकाये बिलों का भुगतान करें। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ व न्यायमूर्ति वीसी दीक्षित की याचिका पर दिया है। याची को वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली व जौनपुर के गांव सभा का पैनाल अधिवक्ता नामित किया गया था। उसे गांव सभा की ओर से नोटिस लेने व प्रतिवाद करने के लिए अधिकृत किया गया था। इस दौरान वाराणसी, गाजीपुर व चंदौली के जिलाधिकारियों

ने याची के बिलों का भुगतान कर दिया, लेकिन जौनपुर के डीएम ने नहीं किया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याची के अधिवक्ता आलोक यादव ने दलील दी कि याची को 16 मई 2013 को चार जिलों की गांव सभा का पैनाल अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। 27 दि. संबर 2019 को हटा दिया गया। बकाया चार लाख 12 हजार दो सौ 75 रुपये 18 फीसदी ब्याज सहित भुगतान किया जाए। कोर्ट ने कहा याची फीस पाने का अधिकार है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

यूपी में भैंस चरा रहे युवक को पुलिस ने थाने में ले जाकर डंडों से पीटा, रिश्त में लिए 1 लाख रुपये

यूपी के बलिया में नरही थाने में तैनात दो पुलिसवालों पर एक लाख रुपये की जबरन वसूली करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। एसपी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। ये वहीं नरही थाना है जहां पिछले दिनों पुलिसकर्मियों द्वारा रा. जाना ट्रकों से लाखों रुपये की अवैध वसूली का भी मामला सुर्खियों में रहा था। बताया जा रहा है कि नरही थाना क्षेत्र में भरौली निवासी रुदल यादव 25 नवंबर को अपने गांव के बागीचे में भैंस को चरा रहा था। तभी थाने पर तैनात सिपाही कौशल पासवान और ऋषिलाल बिंद ने रुदल यादव को उठा लिया और उसे थाने में ले आए। आरोप है कि यहां पर उन्होंने रुबल को एक कमरे में बंद कर दिया और डरा धमका कर उसे छोड़ने के लिए एक लाख रुपये वसूले। जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। जबरन वसूली मामले में दोनों निलंबित पीड़ित रुदल ने इस पूरे मामले की शिकायत एसपी विक्रांत वीर से की। एसपी ने जब मामले की जांच क्षेत्राधिकारी से कराई तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद एसपी ने इन दोनों कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया



और पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दोनों कांस्टेबल को जेल भेज दिया। रुदल का कहना है कि जब वो अपनी भैंस चरा रहा था, तभी दो सिपाही आए और उससे पूछा की तुम्हारा भाई कहां है उस पर मुक. दमा है। ये कहते हुए वो उसे उठा ले गए और थाने में ले जाकर उससे पैसों को मांग करने लगे। उन लोगों ने उसे डंडे से मारा तो उसने एक लाख रुपये मोबाइल से इनके बताए गए व्यक्ति के नंबर पर पैसा भेज दिया उसके बाद उन्होंने उसे थाने से जाने दिया। पीड़ित की शिकायत पर एसपी ने की कार्रवाई एसपी विक्रांत वीर ने इस पर

जानकारी देते हुए बताया कि थाना नरही जनपद बलिया अन्तर्गत एक प्रकरण संज्ञान में आया जहां भरौली के रहने वाले रुदल यादव ने आरोप लगाया गया है कि थाना नरही पर कार्यरत 2 कांस्टेबल कौशल पासवान व ऋषिलाल बिन्द उसे खेत से उठा ले गए और डरा धमकाकर पैसों की वसूली की। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी सदर के द्वारा जांच कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया दोनों आरक्षियों की संलिप्तता पायी गई जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

मठ-मंदिरों को बचाने के लिए बच्चों को क्रांतिकारी बनाएं, अजमेर-संभल विवाद के बीच अखाड़ा परिषद का बयान

अजमेर की दरगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्व विवाद को लेकर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का बड़ा बयान सामने आया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी का कहना है कि अगर हम अपने मठ मंदिरों को नहीं बचा पाए तो आने वाली पीढ़ी हमें कायर समझेगी। उनके मुताबिक ऐसे में जरूरी है कि हम अपने बच्चों में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसा जज्बा पैदा करें। उन्हें क्रांतिकारी बनाएं। बच्चों को शास्त्र के ज्ञान के साथ ही शस्त्र की शिक्षा भी दिया जाना बेहद जरूरी है। हालांकि उनका कहना है कि अजमेर और संभल मामलों से पहले पूरा फोकस काशी और मथुरा को लेकर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों जगह से दुनिया भर के सनातनियों की आस्था और भावना दोनों ही जुड़ी हुई हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर हिंदुओं के कब्जा किए हुए मठ मंदिर उन्हें वापस नहीं मिले तो नागा संन्यासी उन्हें बचाने के लिए खुद मैदान में उतरेंगे और मोर्चा संभालेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने कहा- प्याबर और औ. रंगजेब ने जब भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन पर कब्जा किया था, तब भी देश में बड़ी संख्या में हिंदू रहते थे, लेकिन उस वक्त के हिंदुओं ने उन्हें बचाने के लिए वह कोशिश नहीं की, जिसकी जरूरत थी। इसीलिए आज की पीढ़ी के तमाम लोग उन्हें कायर कहते हैं। आने वाली पीढ़ी हमें कायर ना कहे, इसके लिए जरूरी है कि हमें अपने अंदर वीरता पैदा करनी होगी। हम वीर बनकर ही अपने धार्मिक स्थलों को बचा सकते हैं। धर्म की रक्षा खुद ही करनी होगी- महंत रवींद्र पुरी महंत रवींद्र पुरी ने कहा- प्लानातन धर्म हमेशा सर्वे भवतु सुखिनः यानी सभी के कल्याण की कामना करता है, लेकिन इस कामना के नारे लगाते हुए हम लुट गए- बर्बाद हो गए, ऐसे में अब हमें धर्म की रक्षा खुद ही करनी होगी। अपने धर्म को बचाने के लिए खुद आगे आना होगा। अपने बच्चों को संस्क. रवान बनाने के साथ ही उनके अंदर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस और गुरु गोविंद सिंह जैसा क्रांतिकारी भी बनाना होगा। काशी और मथुरा के मंदिर अभी कहरपंथियों के कब्जे में- महंत रवींद्र पुरी महंत रवींद्र पुरी ने कहा- अजमेर और संभल जैसे मामलों से पहले हमारा पूरा फोकस काशी और मथुरा के मंदिरों को बचाने को लेकर होना चाहिए, काशी और मथुरा के मंदिर अभी कहरपंथियों के कब्जे में हैं। हमने बातचीत के जरिए आस्था के इन दो बड़े केंद्रों को हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन कहरपंथी इन्हें छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं हुए। इन दोनों जगहों से हमारी भावनाएं सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं इसलिए अयोग्यता के राम मंदिर की तर्ज पर पहले इन दोनों मंदिरों को बचाने की कोशिश होनी चाहिए। महंत रवींद्र पुरी ने यह भी कहा है की जरूरत पड़ने पर नागा संन्यासी अपने मठ मंदिरों को बचाने के लिए शस्त्र उठाकर खुद सड़कों पर उतरेंगे और मोर्चा संभालेंगे।



बांग्लादेश में जुमे की नमाज के बाद मंदिरों पर हमला! घर छोड़ भागे हिंदू, प्रशासन बना धृतराष्ट्र

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार जारी है। खासतौर से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। हाल ही में चटगांव में मंदिरों और अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के बाद हिंदुओं को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। शुक्रवार की नमाज के बाद चटगांव में कोतवाली पुलिस स्टेशन के पास कई दुकानों को भी निशाना बनाया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि राधा गोविंदा और शांतनेश्वरी मातृ मंदिर को जमात-ए-इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल लिस्ट पार्टी (बीएनपी) के चरमपंथियों ने निशाना बनाया। यह घटना उस समय हुई जब इलाके में हिंदू धार्मिक संगठन इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को

लेकर एक मार्च निकाला जा रहा था। पुलिस और सेना ने मंदी आंखें, नहीं की मददचश्मदीनों ने बताया कि पुलिस और सेना के जवान हिंदुओं की मदद के लिए आगे नहीं आए और मूकदर्शक बने रहे। यह इलाका मुख्य रूप से हिंदू बहुल है और यहां की 90: आबादी हिंदू समुदाय की है। हिंसा बढ़ने के उर से समुदाय के कई सदस्य इलाका छोड़कर चले गए हैं। अगरस्त में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और देवी-देवताओं को अपवित्र करने और नुकसान पहुंचाने की कई घटनाएं हुई हैं। 200 से ज्यादा मंदिरों को निशाना बनाया गया है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी ने आग में डाला घीहिंदू साधु चिन्मय कृष्ण दास की राजद्रोह के आरोप में



गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद हिंदू समुदाय में भारी विरोध प्रदर्शन

शुरू हो गया है और सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़पें भी हुई हैं। इस्कॉन को भी निशाना बनाया गया है और हाई कोर्ट में

एक याचिका दायर कर इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। बांग्लादेश सरकार ने इसे धार्मिक कट्टरपंथी

संगठन कहा है। हालांकि, कोर्ट ने इस वैश्विक संगठन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। भारत सरकार ने मो. हम्मद यूनुस को लगाई फटकारअल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, भारत ने बांग्लादेश सरकार के समक्ष हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर खतरों और लक्षित हमलों का मुद्दा लगातार और दृढ़ता से उठाया है। हम चरमपंथी बयानबाजी में वृद्धि से चिंतित हैं। हम बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का आह्वान करते हैं।

जयमाला और फेरों के समय नशा करता मिला दूल्हा, दुल्हन ने तोड़ी शादी

साहिबाबाद। होने वाले पति को जब शादी के दिन ही रस्में छोड़कर चोरी छिपे नशा करते पकड़ा तो दुल्हन ने बेबाक होते हुए शादी से इन्कार कर दिया। परिवार ने भी बेटी का साथ दिया और शादी को तोड़ दिया। आरोप है कि इस पर दूल्हा, उसके भाई और बहन ने दुल्हन की मां व अन्य लोगों से हाथापाई कर डाली। डायल 112 की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत कराया। इसके बाद दुल्हन की मां ने होने वाले दूल्हा, उसके भाई, बहन और चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए शादी तय होने से लेकर बारात के दिन तक खर्च हुई रकम को वापस दिलाने की मांग की है। [देहज की मांग पर शादी तोड़ देने के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। इस बार टीएचए के टीला मोड़ इलाके में दूल्हे के नशा करते हुए पकड़े जाने पर शादी टूटने का मामला सामने

आया है। साहिबाबाद के शहीद नगर की रहने वाली शशि ठाकुर ने बताया कि उनकी बेटी अंजलि ठाकुर की शादी दिल्ली गांधी नगर निवासी अविनाश से तय हुई थी। दिल्ली से बारात टीला मोड़ इलाके के साहिबाबाद मार्ग स्थित गोकुल धाम फार्म हाउस पहुंची। दुल्हन पक्ष जयमाला की तैयारी कर रहा था, वहीं दूल्हा बिना किसी को बताए अचानक कहीं चला गया। खोजबीन हुई तो दुल्हन पक्ष के लोगों ने उसे स्टैज के ही पीछे अपने दोस्त के साथ नशा करते हुए पकड़ लिया, लेकिन दूल्हे ने बहाना बना दिया। इसके बाद बारी जब देर रात फेरों की आई तब दोबारा परिवार और दुल्हन ने दूल्हे को गोली व कैप्सूल खाते पकड़ लिया। फिर क्या था दुल्हन ने जब अपने होने वाले पति को नशा करते पकड़ा तो बिना समय गंवाए बेहतर

और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए शादी तोड़ दी। इधर दूल्हा पक्ष ने भी लड़के का साथ देते हुए देहज बतौर दस लाख रुपये की मांग रख दी। जब दुल्हन की मां ने इसका विरोध किया तो आरोप है कि दूल्हे के भाई, बहन और चाचा ने हाथापाई शुरू कर दी। तहरीर में शशि ठाकुर ने बताया कि उन्होंने बेटी की शादी के लिए बड़ी रकम परिचितों और रिश्तेदारों से उधार ली थी। पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए पुलिस से गुहार लगाई है कि शादी के लिए खर्च हुई करीब 14-15 लाख रुपये की रकम उन्हें वापस कराई जाए। एसीपी शालीमार गार्डन सलोनी अग्रवाल ने बताया कि मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कार ने टैंपो में मारी टक्कर, पांच की मौत, छह की हालत नाजुक

श्रावस्ती में भीषण हादसा हो गया। तेज रफतार कार ने टैंपो में टक्कर मार दी। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। जबकि छह लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। यूपी के श्रावस्ती में शनिवार को नेशनल हाईवे-730 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफतार कार ने टैंपो में टक्कर मार दी। हादसे में पांच लोगों की मौत पर ही मौत हो गई। जबकि छह लोगों की हालत गंभीर है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। घायलों को अस्पताल भेजा। हादसा इकोना थाना क्षेत्र के मोहनीपुर तिराहे पर हुआ। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजन को

सूचना दी गई है। हादसे के बाद कार और टैंपो हाईवे किनारे खंती में जा गिरे। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। राहगीर भी रुककर घटना की जानकारी लेने लगे। वहीं गंभीर रूप से घायल कार सवार सहित पांडेय पुरवा निवासी सुबेदार (70) पुत्र हीरालाल, थाना कोतवाली देहात बहराइच के धरसवा निवासी नागेश्वर प्रसाद (48) पुत्र सतगुरु, पयागपुर के वीरपुर सेवनाहे निवासी साकिरा बानो (35) पत्नी सलमान व पांडेय पुरवा निवासी शिवराम (22) पुत्र पाटनदीन को मेडिकल कालेज बहराइच रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को देने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया है।

घटना का सीएम ने लिया संज्ञान जताया दुख

इकोना के मोहनीपुर में हुए सड़क हादसे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के आश्रितों को आर्थिक मदद देने व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने तथा उन्हें आर्थिक सहायता देने को कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने डीएम व एसपी ने तत्काल मौके पर जाकर पीड़ितों की हर संभव मदद करने तथा उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया है।



देवकीनंदन बोले- बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर भारत को देना चाहिए दखल

सनातन बोर्ड गठन के लिए शुक्रवार को संत समाज ने मोतीझील मैदान से हुंकार भरी। सनातन न्यास फाउंडेशन के बैनर तले सनातन संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें शहर व आसपास के क्षेत्रों से महामंडलेश्वर, महंत व संत पहुंचे। सभी ने हिंदू एकता पर जोर दिया। सम्मेलन में पिछले दिनों दिल्ली में हुई सनातन धर्म संसद में रखे गए तीन बिंदुओं पर चर्चा की गई। इनमें मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि अतिक्रमण मुक्ति कराने, सनातन बोर्ड का निर्माण और तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट करने के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। फाउंडेशन के अध्यक्ष देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि किसी भी देश में हिंदुओं के लिए बोलने वाले व्यक्ति का संबंध भारत के सौ करोड़ हिंदुओं से है। कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर भारत को दखल देना चाहिए। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास को



गिरफ्तार किए जाने के मामले में कहा कि अगर सनातन बोर्ड होता तो हम उनकी आवाज उठा सकते थे। कहा कि इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ को पत्र लिखा जाएगा। महामंडलेश्वर उदितानंद महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई अमानवीय घटनाएं न केवल दुर्भाग्यपूर्ण हैं, बल्कि इनसे भारत के

सनातन धर्मावलंबियों को सतर्क रहने की सीख लेनी चाहिए। महामंडलेश्वर ने तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट की घटना को सनातन परंपराओं पर हमला बताया। आनंद भारती ने कहा कि हिंदू समाज को अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होना होगा। महामंडलेश्वर उदितानंद ने कहा कि हमारी संस्कृति और

शादी के 16 बाद बेटी का जन्म, कत्ल करने में नहीं कांपे हाथ

आगरा के एत्मादौला थाना क्षेत्र के कटरा वजीर खां में बेटी खुशी को जहर देकर मारने के बाद पिता चंद्रप्रकाश के आत्महत्या करने की घटना से परिवार में कोहराम मचा है। हर कोई एक ही बात बोल रहा है कि यह कदम उठाने से पहले परिवार से बात क्यों नहीं की। जिस लाडली बेटी के लिए पिता दिन-रात एक किए थे, उसे कैसे मार दिया? पिता ने जिस दिव्यांग बेटी की जान ली, उसका जन्म शादी के 16 साल बाद हुआ। बेटी के लिए न जाने उसने कहां-कहां दुआ मांगी। बेटी से बेइतहा

प्यार भी करता था, लेकिन उसकी जान लेने में उसके हाथ नहीं कांपे। ऐसी क्या मजबूरी रही, इन सवाल के जवाब पिता का आत्महत्या के साथ ही समाप्त हो गए। नगला पदी निवासी सुनील ने बताया कि बहन रेखा की शादी चंद्रप्रकाश से 30 साल पहले हुई थी। 16 साल बाद बहन के बेटी हुई थी। वह ठीक से चल नहीं पाती थी। बहन और बहनोई ने उसे कभी गोदी से उतारने नहीं दिया। दो साल बाद पता चला कि उसके मस्तिष्क का विकास भी उम्र के अनुसार नहीं हुआ है। रिश्तेदारों के घर भी कम

ही जा पाते थे। रेखा को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु के बाद बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी चंद्रप्रकाश पर आ गई। वह भी काम करने कम ही जाते थे। बेटी को पढ़ाने के लिए ट्यूटर रखा। मामा उसे अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन पिता ने बेटी को अपने से अलग नहीं किया। डेढ़ साल पहले चंद्रप्रकाश ने दूसरी शादी की तो फिर से खुशी को लेने मामा गए। मगर, उनका यही कहना था कि बेटी की देखभाल के लिए ही वो शादी कर रहे हैं।

ट्रैक्टर पलटने से प्रधान पति की दबकर

दर्दनाक मौत, मचा कोहराम

फतेहपुर में ट्रैक्टर पलटने से अमनी गांव के प्रधान पति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर ग्रामीणों का लगा तांता लग गया। मामला जिले के विजयीपुर ब्लॉक का है। हादसे में अमनी गांव के प्रधान पति इंद्रलाल यादव की ट्रैक्टर पलटने से दबकर दर्दनाक मौत हो गई।

अग्निवीर भर्ती के लिए कार्यशाला, विंग कमांडर करेंगे मार्गदर्शन

फतेहपुर। राजकीय इंटर कॉलेज में 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे से जिला सेवायोजन कार्यालय की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसमें अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती के लिए विंग कमांडर आनंदन गुणशेकर अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। कार्यशाला में हाईस्कूल व इंटर उर्तीण सभी इच्छुक छात्र-छात्राएं प्रतिभाग कर सकते हैं। 2 दिसंबर को विकासखंड बहुआ, 3 को तेलियानी, 4 को धाता और 5 को खुजुहा में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला सेवायोजन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।



अदालत ने डीजीपी को भेजा पत्र और गैर जमानती वारंट, कड़ा- बिल्डर को कड़ा पेश

अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरेशी की ओर से पत्र डीजीपी को भेजा गया है। जिसमें उन्होंने क्वालिटी डेवल. पर्स ऑफिस स्टारलिंग होम अनूपशहर रोड के मालिक कमर खान के खिलाफ 19 जनवरी से आदेश का पालन न किए जाने पर गैर जमानती वारंट जारी होने का जिक्र किया है। अलीगढ़ शहर के एक बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता अदालत ने जनवरी से गैर जमानती वारंट जारी कर रखे हैं। थाना पुलिस से लेकर डीआईजी तक को लगातार पत्राचार के बाद भी वह न्यायालय में पेश नहीं हुए। अब डीजीपी को गैर जमानती वारंट के साथ पत्र भेजा गया है। इस संबंध में जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरेशी की ओर से पत्र डीजीपी को भेजा गया है। जिसमें उन्होंने क्वालिटी डेवल. पर्स ऑफिस स्टारलिंग होम अनूपशहर



CONSUMER PROTECTI

रोड के मालिक कमर खान के खिलाफ 19 जनवरी से आदेश का पालन न किए जाने पर गैर जमानती वारंट जारी होने का जिक्र किया है। इस संबंध में थाना क्वार्सी, एसएसपी व डीआईजी तक को पत्र व वारंट भेजे गए हैं। मगर बिल्डर को गिरफ्तार कर आज तक पेश नहीं

किया जा सका। जबकि वह अन्य मुक. दमों में अधिवक्ता के जरिये लगातार न्यायालय में हाजिरी दर्शा रहा है। ऐसे में कहा गया है कि आप अपने स्तर से जिला पुलिस को निर्देशित कर बिल्डर कमर खान को 5 दिसंबर को पेश कराएं।

डीडीयू अस्पताल यहां ना आए दिल, दांत और कान के बीमार, तीन साल से नहीं है इनके चिकित्सक

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल अलीगढ़ के बड़े अस्पतालों में शामिल हैं। लेकिन बदहाल व्यवस्था के चलते यहां लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। यहां न तो चेस्ट फिजिशियन है, न ही डेंटिस्ट। कॉर्डियोलॉजिस्ट और ईएनटी भी नहीं हैं। ऐसे में लोगों को प्राइवेट नर्सिंग होम की दौड़ लगानी पड़ती है। जिससे लोगों को सस्ता इलाज नहीं मिल पा रहा था। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सभी विभागों में चिकित्सकों की तैनाती के लिए शासन से मांग की जा रही है। डीडीयू अस्पताल में भी मोहनलाल गौतम महिला जिला अस्पताल की तरह मरीज के ऑपरेशन के दौरान मलखान सिंह जिला अस्पताल से एनेस्थीसिया डॉक्टर को बुलाया जाता है। डीडीयू अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 1200-1500 मरीज आते हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी है। यह स्थिति कोई एक दो महीने से नहीं बल्कि तीन साल से चि. कत्सक नहीं है। लेकिन इस पर फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए आए थे। मगर डॉक्टर नहीं मिले। मुझे बोला गया कि डॉक्टर का इंतजार करें।—योगेश कुमार, डिबाईबच्चे की सांस में दिक्कतें थीं, जिसे दिखाने के लिए सुबह 8 बजे अस्पताल आई थीं। दोपहर 2 बजे गए, लेकिन डॉक्टर नहीं आए।—उर्मिला, मंदिर का नगला सुबह आठ बजे से 2रु30 बजे तक डॉक्टर का इंतजार करने के बाद डॉक्टर ने देखा। ऑपरेशन के इंतजार में बैठना पड़ रहा है।—बिन्दा देवी, बरौठाओपीडी में जिस तरह मरीजों की तादाद होती है, उस हिसाब से डॉक्टरों की कमी है। शासन को डॉक्टरों की तैनाती के लिए पत्र लिखा जा चुका है।—डॉ. एमके माथुर, सीएमएस, डीडीयू अस्पताल



वेल्लिंग की चिंगारी से गोदाम सहित तीन दुकानों में लगी भीषण आग, मची भगदड़

अलीगढ़ में थाना देहलीगेट क्षेत्र के बारहद्वारी स्थित किलाटगंज में 29 नवंबर दोपहर डिस्पोजल सामान के गोदाम, मसाले की दुकान और ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में भीषण आग लग गई। तीन जगहों पर आग की खबर पर आस-पास के दुकानों में खलबली मच गई। हादसा पड़ोस में ट्रांसपोर्ट के गोदाम में चल रही मरम्मत के दौरान वेल्लिंग की चिंगारी निकलने से होना बताया जा रहा है। दमकल कर्मियों ने घंटे भर की मशकत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। दे. हलीगेट इलाके के मोहल्ला कटरा स्ट्रीट निवासी आकाश वार्षण्य की खैर रोड पर आकाश डिस्पोजल के नाम से दुकान और किलाटगंज में गोदाम है। पास में ही अलीगढ़-हाथरस ट्रांसपोर्ट कंपनी और पवन अग्रवाल की मसाला पिसाई की दुकान है। पुलिस के अनुसार 29



नवंबर को ट्रांसपोर्ट के गोदाम में मरम्मत का कार्य चल रहा है। एक युवक वेल्लिंग करने आया था। उसी समय चिंगारी पास के गोदाम में चली गई। गोदाम का ताला बंद था। आग धीरे-धीरे सुलगती रही। स्थानीय लोगों ने गोदाम से धुआं उठता देखा तो शक हुआ। देखने पर गोदाम में आग लगने की जानकारी हुई इस बीच आग विक. राल हो गई और उसने ट्रांसपोर्ट के गो. दाम के साथ ही डिस्पोजल व मसाले की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में गोदाम व दोनों दुकानों का सामान जलकर राख हो गया। हादसे की खबर पर दमकल तीन गाड़ियों ने मौके पर आकर आग पर काबू पा लिया। आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

तहसील मुख्यालयों तक चलेंगी अब ई-बस, हरदुआगंज से अतरौली तक चलेंगी बसें

अलीगढ़ में ई बस को लेकर अच्छी खबर आई है। गभाना व इगलास तक संचालन पहले से ही किया जा रहा है। नए प्रस्ताव के तहत हरदुआगंज तक चलने वाली बसों का सेवा विस्तार करते हुए उन्हें अतरौली तक संचालित किया जाएगा। नादापुल खरेश्वर तक जाने वाली बसें खैर तक चलेंगी। अलीगढ़ शहर के साथ ही ग्रामीण यात्रियों को भी ई-बस सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। रोडवेज अफसरों ने जिला मुख्यालय से अतरौली एवं खैर तक इन बसों के संच. लान का प्रस्ताव तैयार किया है। गभाना व इगलास तक संचालन पहले से ही किया जा रहा है। नए प्रस्ताव के तहत हरदुआगंज तक चलने वाली बसों का सेवा विस्तार करते हुए उन्हें अतरौली तक संचालित किया जाएगा। नादापुल खरेश्वर तक जाने वाली बसें खैर तक चलेंगी। इसके लिए विभागीय अफसरों ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को चार दिसंबर को कमिश्नर चौत्रा वी. की अध्यक्षता वाले बोर्ड के समक्ष मंजूरी



के लिए रखा जाएगा। बोर्ड से संचालन पर अंतिम निर्णय होगा। महानगर में छह अलग-अलग मार्गों पर ई- बसों का संचालन किया जा रहा है। अतरौली क्षेत्र में ग्रामीण लगातार ई-बसों के संचालन की मांग करते आ रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने भी संबंधित अफसरों को पत्र भेजकर प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिए थे। नए प्रस्ताव के तहत जिला मुख्यालय से लेकर जिले की सभी पांचों तहसील मुख्यालयों तक बसें संचालित की जाएगी। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक बसों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। इसे कमिश्नर की अध्यक्षता वाले स्मार्ट सिटी बोर्ड के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। मंजूरी मिलते ही इनका संचालन शुरू कर दिया जाएगा।

भारतीय हलधर किसान यूनियन द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन



भारतीय हलधर किसान यूनियन की एक प्रेस वार्ता साईं रेस्टोरेंट स्वर्ण जयन्ती नगर में सम्पन्न हुई जिसमें किसान भाइयों की समस्या को ध्यान में रखते हुये किसान हेल्प लाइन न० 9634801545 जारी किया जिस पर जनपद के किसान भाइयों की समस्याओं को सुना जायेग एवं समाधान करने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा एवं श्री मेघ सिंह जी (जिला उपाध्यक्ष), श्री मनोज कुमार (जिला सचिव नियुक्त किया गया है। इस मौके पर श्री जी प्रधान जी (प्रदेश महासचिव),

श्री गोरख दुवे (जि०ध्यक्ष व्यापार भो चर्चा) श्री रंजीत चौधरी जी (तहसील उपाध्यक्ष), श्री सत्येंद्र कुमार जी (मळल उपाध्यक्ष), श्री पुजीत शर्मा जी (मुख्य महासचिव) श्री राजेंद्र चौधरी जी (सदस्य), श्री सोनू सकिता जी. श्री धवलू सैनी जी, श्री दुर्गापाल सिंह जी (जिला उपाध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ) श्री सूरज चौधरी जी (क्लाक अध्यक्ष), श्री मान सिंह तोमर जी (जिलाअध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ), श्री निर्मल जी एवं श्री राजू मी (सदस्य) एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

महाकुंभ के लिए थाली-थैला अभियान शुरू, अलीगढ़ डीएम ने की सराहना अलीगढ़ में आरएसएस की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की ओर से विभाग सह संघचालक ललित कुमार, विभाग कार्यवाह योगेश आर्य, विभाग संयोजक विकास शर्मा ने डीएम से मुलाकात कर थाली और थैला अभियान की शुरुआत की। अभियान से जुड़ने का आग्रह भी किया। डीएम ने इस अभियान की सराहना की। सह विभाग संघचालक ललित ने बताया कि महाकुंभ में विश्व के 50 से अधिक देशों से श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में पर्यावरण का संदेश पूरी दुनिया तक जाना चाहिए। विभाग कार्यवाह योगेश आर्य ने कहा कि अगले वर्ष 13 जनवरी से प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ेगा। ऐसे में घर घर से थाली और थैला यदि महाकुंभ में भेजा जाएगा तो मेले में पॉलिथिन और अन्य कचरा नहीं होगा। इस अवसर पर बृज प्रांत की नारी शक्ति सह प्रमुख डाक्टर नीलम श्रीवास्तव, गतिविधि संरक्षक अनिल अग्रवाल एवं महानगर संयोजक जितेंद्र गर्ग मौजूद रहे।

सीडीओ की अध्यक्षता में जिलास्तरीय उद्योग व व्यापार बन्धु बैठक संपन्न

अलीगढ़ 30 नवंबर 2024 (सु०वि०)रु मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग एवं व्यापार बन्धु बैठक का आयोजन किया गया। सीडीओ ने कहा कि उद्यमी और व्यापारी किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ होते हैं, ऐसे में शासन के साथ ही जिला प्रशासन की भी मंशा है कि जिले में औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में रोजगार के और अधिक अवसर सृजन करने के लिए नई औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाईयों की स्थापना में हर संभव सहयोग प्रदान किया जाए। सीडीओ ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप अपने विभागीय क्षेत्र से उद्यम स्थापना एवं उनके सफल संचालन के लिए जो भी सहयोग कर सकते हैं प्रदान करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी उद्यमी के प्रस्ताव या आवेदन में कोई कमी है तो उसे नियमों की जानक. री देते हुए सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान औद्योगिक क्षेत्र तालानगरी में विद्युत आपूर्ति को पंचम सब स्टेशन से जोड़े जाने एवं 131 केबीए उपकेंद्र की स्थापना के संबंध में अधिशासी अभियंता तृतीय विद्युत ने बताया कि 131 केबीए विद्युत उपकेंद्र पंचम पर 33 केबी यूपीएसआ. ईडीसी की 33 केबी सीटी स्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। तालानगरी को विद्युत उपकेंद्र बौनेर से जोड़ने के लिए तकनीकी अनुमोदन हेतु प्रबंध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। दाऊद खॉं स्टेशन के निकट



स्टफिंग सेंटर की स्थापना के संबंध में अवगत कराया गया कि उद्यमियों की मांग पर डीएफसीसीआईएल भारतीय रेलवे की जीएसटी नीति के तहत सार्वजनिक निजी भागेदारी के साथ न्यू दाऊद खॉं में फ्रेट टर्मिनल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 2.7 किलोमीटर पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण के लिए यूपीसीडा का पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त प्रकरण में सीडीओ ने उपायुक्त उद्योग को यूपीसीडा के अधिकारियों से वार्ता कर स्थिति स्पष्ट करने के साथ ही अन्य संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा में बताया गया कि पोर्टल के माध्यम से 45 विभागों की 454 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। विगत माह में जिलास्तर पर 364 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से कोई भी प्रकरण समय सीमा के उपरांत लंबित नहीं है और न ही किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकरण को समय सीमा के उपरांत

निरस्त व स्वीकृत किया गया है। बैठक में औद्योगिक आस्थान की ओर जाने वाली सड़क की मरम्मत एवं समुचित प्रकाश व्यवस्था के संबंध में उद्यमियों द्वारा सामूहिक रूप से कहा गया कि 2 माह बाद प्रदर्शनी का भी आयोजन होना है ऐसे में प्रदर्शनी से पूर्व सड़क एवं प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करा दिया जाए। उद्यमियों द्वारा नगर निगम क्षेत्र में आए नवीन परिवारों पर लगाए गए टैक्स पर ब्याज में छूट प्रदान किए जाने, नगर की यातायात व्यवस्था के साथ वाहनों के बेतरतीब संचालन से आए दिन हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। सीडीओ ने यातायात से संबंधित प्रकरण को सड़क सुरक्षा की बैठक में रखने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त उद्योग बीरेन्द्र कुमार समेत उद्यमी नेकराम शर्मा, सतीश माहेश्वरी, चन्द्रशेखर शर्मा, लल्लू सिंह, एन०के० खान गॉंधी, प्रदीप गंगा, दिनेश चन्द्र वार्षण्य सहित संबंधित अधिक. रीगण उपस्थित रहे।

यूपी पुलिस को SC की फटकार

नई दिल्लीरु सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी पुलिस को जैसी कड़ी फटकार लगाई है, उससे जाहिर होता है कि मर्ज पुराना है और गंभीर भी। देश की शीर्ष अदालत को अगर यहां तक कहना पड़े कि पुलिस पावर का आनंद ले रही है और उसे संवेदनशील होने की जरूरत है, तो इसका मतलब कि खाकी उन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही, जिसके लिए उसे इतनी शक्तियां दी गई हैं। अदालत की टिप्पणी फिर से याद दिला रही है कि देश में पुलिस सिस्टम में सुधार की कितनी जरूरत है। समाज के एक बड़े तबके में पुलिस के लिए आदर नहीं, डर का भाव है। उसे थाने में जाकर अपनी बात कहने से डर लगता है। हम बात करते हैं कि आम जन पुलिस के साथ सहयोग करें, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक कि आम जन का पुलिस पर भरोसा ही नहीं होगा। इसकी वजह है पुलिसिया कार्यप्रणाली, जो अभी तक औपनिवेशिक मानसिकता में जकड़ी दिखाई देती है। और इसकी वजह से कानून नहीं, डर का शासन ज्यादा दिखता है। फाइलों में बंद सुझाव सवाल यह भी है कि पुलिस इस मानसिकता से निकलेगी कैसे, जबकि उसकी बुनियाद में अब भी 1861 का वही पुलिस एक्ट है, जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पर राज करने के लिए बनाया था। डेढ़ सौ बरस से ज्यादा हो गए और इस दौरान देश-समाज ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन उसकी तुलना में पुलिस सिस्टम वहीं ठहरा हुआ लगता है। कहने को सिस्टम में सुधार के लिए 1977 में नेशनल पुलिस कमिशन बना, रिबेरो समिति, पद्मनाभैया समिति, मलिमथ समिति आई, लेकिन किसी के भी सुझावों पर पूरी तरह अमल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 2006 में पुलिस सुधारों के लिए कुछ दिशा-निर्देश दिए थे। इसमें कहा गया था कि स्टेट सिक्योरिटी कमिशन का गठन हो और डीजीपी समेत दूसरे अफसरों को भी कम से कम दो साल का मौका मिले। इनका मकसद यह था कि पुलिस को राजनीतिक दबाव से निकाला जाए, ताकि वह स्वतंत्र रूप से काम कर सके। कहने की जरूरत नहीं कि इन पर अमल नहीं हुआ। मार्च 2023 में सरकार ने संसद में जानकारी दी थी कि देश में प्रति एक लाख आबादी पर औसतन केवल 152.80 पुलिसकर्मी हैं। यूपी में तो यह आंकड़ा और भी कम था, महज 133.86। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूरे देश की पुलिस दबाव में है। सीनियर्स का प्रेशर, काम के घंटे, छुट्टियों की कमी- कुल मिलाकर यह स्थिति उस डिपार्टमेंट के लिए सही नहीं कही जा सकती, जिस पर सुरक्षा जैसी अहम जिम्मेदारी है। हम यह तो सोच रहे हैं कि पुलिस सुधर जाए, लेकिन यह भी सोचना होगा कि उनके काम का माहौल सुधरे। दोनों चीजें साथ होंगी, तभी परिणाम बेहतर मिलेगा।

ज्ञान के दरवाजे खोलने की पहल, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना मंजूर

डा. ब्रजेश कुमार तिवारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों देश भर के छात्रों को विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशन तक आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) नामक एक नई योजना को मंजूरी दी। इस योजना के माध्यम से देश के लगभग 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता विश्व स्तर पर प्रकाशित हो रहे 13,000 से अधिक ई-जर्नल तक आसान पहुंच हासिल कर सकेंगे। ओएनओएस योजना केवल प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी रहने वाले छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को भी वैश्विक स्तर पर सृजित हो रहे ज्ञान का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करेगी। इससे पहले जर्मनी और उरुग्वे सरकारों ने अनुसंधान सामग्री तक समान राष्ट्रीय पहुंच की शुरुआत की थी। वास्तव में वैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रगति तभी प्राप्त की जा सकती है, जब वैश्विक ज्ञान तक पहुंच सुलभ हो। अनुसंधान एवं विकास ही हम सभी के लिए बेहतर जीवन का द्वार खोलती है। भारत पिछले कुछ वर्षों में श्रम-आधारित अर्थव्यवस्था को कौशल-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने में काम कर रहा। 15 अगस्त, 2022 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की प्रगति में अनुसंधान और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की थी और जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान जोड़ा था। सरकार की यह पहल गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा एवं शोध तक शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की पहुंच को आसान बनाएगी। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विकसित भारत और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लक्ष्यों के अनुरूप है, जो भारतीय शिक्षा जगत और युवा सशक्तीकरण के लिए गेम-चेंजर साबित हो। इस योजना का लक्ष्य उन संस्थानों के लिए शोध पत्रिकाओं तक पहुंच का विस्तार करना है, जिनके पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। यह प्लेटफॉर्म एक जनवरी, 2025 को शुरू होने वाला है। इस मंच पर एल्सेवियर साइंस डायरेक्ट (लैंसेट सहित), स्प्रिंगर नेचर, विली ब्लैकवेल पब्लिशिंग, टेलर एंड फ्रांसिस, आइईईईई, सेज पब्लिशिंग, अमेरिकन केमिकल सोसायटी, अमेरिकन मैथेमेटिकल सोसायटी, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस और बीएमजे जर्नल्स सहित 30 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 13,000 पत्रिकाएं उपलब्ध होंगी। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत दस अलग-अलग पुस्तकालय संघ हैं, जो अपने प्रशासनिक दायरे में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं। इसके अलावा अलग-अलग संस्थान अलग-अलग पत्रिकाओं की सदस्यता लेते हैं। वैज्ञानिक पत्रिकाओं की सदस्यता एक महंगा मामला है। ओएनओएस के आरंभ होने से यह बहुत सस्ता हो जाएगा। एक ही मंच पर सारी पत्रिकाएं उपलब्ध होने से शोधार्थियों को भ्रम नहीं पड़ेगा। एक आंकड़े के अनुसार भारत ने 2018 में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट पत्रिकाओं की सदस्यता पर लगभग 1,500 करोड़ रुपये खर्च किए थे। शोध अंतर्दृष्टि डाटाबेस स्क्वल के अनुसार 2017 और 2022 के बीच भारत के शोध प्रकाशन में लगभग 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वैश्विक औसत (22 प्रतिशत) के दोगुने से भी अधिक है। भारत का शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन में चौथा स्थान (13 लाख अकादमिक पेपर) रखता है, जो चीन (45 लाख), अमेरिका (44 लाख) और ब्रिटेन (14 लाख) के ठीक बाद है, परंतु जब उत्पादित शोध के प्रभाव की बात आती है, तो उद्धरणों (साइटेशन) की संख्या में भारत पीछे रह जाता है और दुनिया में नौवें स्थान पर आता है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फार कांफिडेंटियलनेस द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत का अनुसंधान एवं विकास पर यह खर्च दुनिया में सबसे कम है। देश की नवाचार सफलता में एक और बाधा अनुसंधान एवं विकास कर्मियों की कम संख्या है। यूनेस्को इंस्टीट्यूट आफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्रति दस लाख आबादी पर केवल 253 विज्ञानी या शोधकर्ता हैं, जो विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफी कम है। निजी क्षेत्र का योगदान अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय का 40 प्रतिशत से कम है, जबकि उन्नत देशों में यह 70 प्रतिशत से अधिक है। दुनिया में अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करने के मामले में शीर्ष 2,500 वैश्विक कंपनियों की सूची में केवल 26 भारतीय कंपनियां हैं। जबकि चीनी कंपनियों की संख्या 301 है। इस अंतर को प्राथमिकता के आधार पर पाटने की आवश्यकता है। चीन का मुकाबला करने के लिए उससे सीख लेने में हर्ज नहीं। इजरायल से भी सीख ली जानी चाहिए, जिसने यह दिखा दिया है कि एक छोटा राष्ट्र होने के बावजूद अनुसंधान एवं विकास में निवेश को प्राथमिकता देकर सतत विकास हासिल किया जा सकता है। भारत में निजी कंपनियों मुख्य रूप से बिक्री और विपणन में निवेश करती हैं और अनुसंधान एवं विकास में पर्याप्त संसाधनों का निवेश नहीं करती हैं। यही कारण है कि भारतीय ब्रांड नवाचार नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते भारतीय निर्माता विश्व स्तर पर अनुकरणीय उत्पाद नहीं बना रहे हैं और विश्व बाजार में चीनी कंपनियों की चुनौती का सामना नहीं कर पा रहे हैं। अब समय आ गया है कि मेक इन इंडिया के लिए अनुसंधान एवं विकास पर फिर से ध्यान केंद्रित किया जाए। भारत के पास नवाचार का वैश्विक चालक बनने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां, एक मजबूत बाजार क्षमता, असाधारण प्रतिभावान आबादी और मितव्ययी नवाचार की एक संपन्न संस्कृति हैं। जरूरत है तो कच्ची प्रतिभाओं की खान को सही मार्गदर्शन की। वास्तव में एक मजबूत अर्थव्यवस्था होने के लिए देश के पास दीर्घकालिक और सार्थक स्तर पर ज्ञान प्रणाली की आवश्यकता है, जो अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करती है। जितनी बौद्धिक संपदा सृजित होगी उतने बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे।

संपादकीय : तड़प रही है प्रजा



महाराष्ट्र में विधानसभा में जीत के बाद भाजपा और उसकी महायुति में आनंद ही आनंद है। सभी ने महाराष्ट्र में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। इसमें शिंदे सेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी भी है। इस मंडली का कहना है कि लोगों ने मोदी को देखकर वोट दिया है। इस खुशी का जश्न दिल्ली में मोदी समर्थकों ने भी मनाया, लेकिन क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी देश के युवाओं और किसानों के जीवन में आनंद लाने में सफल रहे हैं? आज देश पर रोजगार का महासंकट आ गया है। देश की आबादी १४० करोड़ है, उनमें से चालीस प्रतिशत हताश-निराश बेरोजगार हैं। मोदी ने ८१ करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त सरकारी राशन देकर पेट भरने की व्यवस्था की है। इसका मतलब है कि देश में ८१ से ८२ करोड़ लोग बेरोजगार हैं। मोदी ने उन्हें मुफ्त राशन देने का उपाय निकाला है। जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। १४ प्रमुख राज्यों में बेरोजगारी चरम पर है, इसमें पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं। महाराष्ट्र में केवल १६ प्रतिशत लोगों के पास रोजगार है और बाकी लोग खाली हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती, सार्वजनिक उपक्रमों में भर्ती बंद है। लगभग २५ लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं और पेपर लीक घोटाले के चलते लाखों नौकरियां अटक पड़ी हैं। जब भर्ती निकलती है तो हर पद के लिए हजारों आवेदन आते हैं। भर्ती स्थल पर बेरोजगारों की भगदड़ मच जाती है। शिक्षक, पुलिस, होम गार्ड की भर्ती के दौरान पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ती हैं। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर मोदी 'अग्निवीर' जैसी एक खोकली योजना लाये जो विफल रही। भारतीय सेना में कांट्रैक्ट पर लोगों को नियुक्त करने की उनकी योजना वाकई अनोखी ही थी। मोदी सरकार ने अकुशल श्रमिकों को इजरायल में काम करने के लिए भेजने की योजना की घोषणा की, लेकिन ये नौकरियां भारतीय युवाओं को मौत की खाई में धकेलने वाली साबित हुई। इजरायल में नौकरी

देना अमानवीय था। वह भी असफल रही। सरकार का कहना है, देश में बेरोजगारी कम हुई है और लोगों का बढ़िया चल रहा है। जिनके पास रोजगार है, उनमें से ७८ फीसदी १५ हजार प्रति माह से कम कमाते हैं। स्वरोजगार करनेवालों की आय ८ हजार से कम है। क्या अब मोदी सरकार इन सभी को भी मुफ्त सरकारी राशन देगी? देश में अब राजगार, नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं। क्योंकि देश में उद्योग के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। ईडी, सीबीआई, भाजपा और इनकम टैक्स के आतंक से देश के ५ लाख से ज्यादा मझोले उद्यमी पलायन कर गए और उन्होंने दूसरे देशों में जाकर निवेश किया है। इससे बहुत सारी नौकरियां बाहर चली गईं। गौतम अडानी नामक एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द देश की अर्थव्यवस्था और उद्योग क्षेत्र घूम रहा है, लेकिन पूरे अडानी समूह में देश में दो हजार लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है और अडानी को देश की सार्वजनिक संपत्ति का मालिक बना दिया गया है। आजादी के बाद टाटा, बिड़ला, बजाज, प्रेमजी, वाडिया, नारायण मूर्ति जैसे कई लोगों ने देश में निवेश किया और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हुआ। पंडित नेहरू ने कई सार्वजनिक उद्यमों की नींव रखी और उनके माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया। मोदी काल में ये सभी सरकारी उपक्रम ध्वस्त हो रहे हैं। मुंबई जैसे सर्वाधिक रोजगार देनेवाले औद्योगिक शहर के महत्व को कम कर दिया गया है। ऐसा दिख रहा है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में उद्योगों को आने से ही रोकने के लिए लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। आज बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल में नौकरियों की कमी है और मुंबई समेत महाराष्ट्र भी नौकरियों के नाम पर 'न-न गोपाल' है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके लोग कभी गरीबी, राजगार और महंगाई पर बात करते नहीं दिखते। क्योंकि सभी क्षेत्रों का रोजगार खत्म हो गया है। मोदी काल में जिस तरह का विस्फोटक और भयावह माहौल बना है, उसका पर्यटन उद्योग पर गहरा असर पड़ा है। इसमें मुख्य रूप से

जम्मू-कश्मीर, उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं। मोदी बुलेट ट्रेन का सपना देखते हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब से 'हवाई' यात्रा करेगा। इस तरह के भाषण निकते हैं, लेकिन हकीकत में जमीनी हालात जुदा और खौफनाक हैं। यूक्रेन, इराक, ईरान, अफगानिस्तान जैसे देश युद्ध की स्थिति के कारण बेरोजगारी और भुखमरी से पीड़ित हैं। भारत में ऐसी कोई बात नहीं है फिर भी 'बेरोजगारी' का ज्वालामुखी फूट पड़ा है और शासक चुनावी जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र जीत लिया। पिछले ढाई साल में महाराष्ट्र में पांच हजार से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बेरोजगारों ने निराशा में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महाराष्ट्र समेत पूरे देश की मौजूदा स्थिति वैहसी है? इस पर मराठी में कुछ पंक्तियां हैं: तळमळे अवधी प्रजा, उत्तसी मग्न राजा साधितो शकुनि काजा। वैरी घर भरिती स्वैरगति रमिति। प्रजानन फिरती रानी। (अर्थात् राजा खुश है उत्सव में मग्न है और प्रजा परेशान है, तड़प रही है।) बोलो, जय श्रीराम !

आवश्यकता है

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र जननायक सम्राट के लिए जिला व्यूरो चीफमंडल व्यूरो चीफ ब्लाक, व्यूरो संवाददाता की आवश्यकता है। सम्पर्क करें - अमित कुमार वर्मा -संम्पादक मो:-8218049162,8273402499

जननायक सम्राट

हिन्दी साप्ताहिक मालिक,मुद्रक, प्रकाशक आरती वर्मा द्वारा आशु प्रिटिंगप्रेस,अचलताल अलीगढ़ से मुद्रितकराकर कार्यालय सरोज नगर गली नम्बर 5,अलीगढ़ से प्रकाशित सम्पादक-अमित कुमार वर्मा सभी विवाद का न्याय क्षेत्र जनपद अलीगढ़ न्यायलय ही होगा

